Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to restart the Additional Central Assistance scheme for Left-Wing Extremism affected districts in Bihar.

श्री सुशील कुमार सिह (औरंगाबाद)ः देश के वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित विभिन्न प्रांतों के करीब 82 जिलों में भारत सरकार द्वारा विकास की योजना, समेकित कार्य योजना (IAP) चलाई गयी थी। इसका नाम बदलकर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) किया गया। इन योजनाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 30 करोड़ रूपये आवंटित होते थे और इसके अंतर्गत बिहार के 11 चयनित जिले थे, जिसमें हमारे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिले भी शामिल थे। पूर्व में जनप्रतिनिधियों के सुझावों ओर अनुशंसाओं पर जिले में गठित समिति द्वारा (LWE) क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती थी मेरे द्वारा मामले को पूर्व में सदन में उठाया गया, परन्तु इस संबंध में अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं की गई है।

यद्यपि समेकित कार्य योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के तहत विकास योजनाओं के चयन हेतु गठित समिति में किसी भी जनप्रतिनिधि/विधायक को शामिल नहीं किया गया है, पूर्व में जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर कुछ कार्य होते थे जिससे पिछड़े और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की किरणें पहुंचाकर नक्सल समस्या के नियंत्रण अथवा समाधान में बड़ी भूमिका निभाई जाती थी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि समेकित कार्य योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को पुनः प्रारम्भ किया जाए, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित जिलों को धन उपलब्ध कराया जाए और उक्त आवंटित राशि का खर्च निर्वाचित जनप्रतिनिधियों विशेषकर सांसदों की अनुशंसा पर किया जाए और इसे कानून के तहत शामिल किया जाए ताकि उग्रवाद प्रभावित राज्यों का सम्यक विकास हो।